भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1348

08.12.2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में प्रदूषण के लिए धनराशि का उपयोग

1348. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए आवंटित धनराशि का 1 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया गया;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में वायु, जल और औद्योगिक प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बावजूद निधियों का इतना कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में प्रदूषण नियंत्रण उपायों हेतु आवंटित, जारी और वास्तव में उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में धनराशि के कम उपयोग की वजह से प्रदूषण कम करने की कोई विशेष परियोजना में देरी हुई या निरस्त हो गए; और

(ङ) सरकार द्वारा आवंटित धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और महाराष्ट्र में प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निधि सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध कुल निधि में से, कुल 686.26 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 80% निधि शामिल है।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए XV वें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत प्रदान किए गए 1555.34 करोड़ रुपये सहित महाराष्ट्र के 19 शहरों को 1794.86 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। महाराष्ट्र राज्य ने 80% निधि के उपयोग की सूचना प्रदान की है।

निधि के उपयोग सहित शहरी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने के लिए एनसीएपी के तहत गठित की गई समितियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****